

जनजातीय क्षेत्र में समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता पद्धति (CLTS) हस्तक्षेप के प्रभाव का अध्ययन

¹डॉ कृष्ण कुमार तिवारी

²छोटे लाल

शोध सारांश :-

देश भर में स्थायी और बड़े पैमाने पर स्वच्छता आवृत्ति के लिए समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता (सी.एल.टी.एस.) को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना प्रारंभ की जिसका लक्ष्य था कि आगामी पांच वर्ष में 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण देश को खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) बनाना है। इसलिए समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता (सी.एल.टी.एस.) कार्यान्वयन के दौरान होने वाले व्यवहार परिवर्तन को समझना अनिवार्य है। रणनीतियों, चुनौतियों और अभिनव समाधानों को समझने का प्रयास करता है। सामुहिक व्यवहार परिवर्तन को उत्प्रेरक करने वाले प्रमुख चालक और राजनांदगांव के आदिवासी ब्लॉक तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम सुनिश्चित करने का उपाय है। ओ.डी.एफ. समुदाय के 70 लोगों को पहली बार शौचालय उपयोग करने तथा अनुभवों की जानकारी की जांच करता है। जिन्होंने खेतों, जंगलों में शौच करना बंद कर दिया और अपने घर के पास बने शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। साक्षात्कार और जांच के माध्यम से आंकड़े संग्रहण किया गया है जो उत्तरदाताओं के शौचालय के लाभों एवं अनुभवों को वर्गीकृत करता है। समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता (सी.एल.टी.एस.) के सफल क्रियान्वयन एवं साफ-सफाई संचालन के निष्कर्ष को समझा जा सकता है।

मुख्य शब्द :- स्वच्छता, समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता (सी.एल.टी.एस.)

¹सहायक प्राध्यापक समाज कार्य मैट्र्स विश्वविद्यालय रायपुर

²शोध छात्र समाज कार्य मैट्र्स विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़

भूमिका

2 अक्टूबर, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) SBM (G) के शुभारंभ के समय जिले का स्वच्छता आच्छादन 60: से कम था। पूर्व में निर्मल ग्राम पंचायत/ग्राम के नाम से जाना जाता था। 2014 के बाद 94: गांवों को खुले में शौच मुक्त किये

जाने का बड़ा लक्ष्य था। दुनिया भर में समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता (सी.एल.टी.एस.) के प्रभाव और परिणाम एक मात्र विकल्प था। सामुदायिक स्तर पर सी.एल.टी.एस. के त्वरित और प्रभावी परिणामों ने यह साबित कर दिया था कि कैसे चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। यह सहभागी और सशक्त दृष्टिकोण होने के नाते सामुदायिक स्तर पर समुदाय को इस प्रकार जोड़ता गया और लोगों की जागरूकता के माध्यम से खुले में शौच करने के प्रथा को समाप्त करने के लिए सामूहिक स्थानीय कार्यवाही को प्रेरित करना है। सी. कुमार और शुक्ला 2011 युनिसेफ द्वारा समर्पित सी.एल.टी.एस. हस्तक्षेप के उपकरणों और तकनीकों को अन्य सामाजिक प्रतिबंधता विधियों के साथ जोड़कर समायोजित करने की मांग किया जिसके विभिन्न स्तरों पर लोगों को जुड़ाव सुनिश्चित हो सके विश्वसनीय खुले में शौच मुक्त ओ.डी.एफ. करने की परिणाम तेजी से और बड़े पैमाने पर प्राप्त हो सके। ओ.डी.एफ. ग्राम बनाने की रणनीति में क्षमता निर्माण, संस्थागत सुदृढीकरण और गांव में चौपाल लगाकर ओ.डी.एफ. बैठक किया जाता था। फरवरी 2015 के दौरान जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को प्रभावी ढंग से लगाकर करने में मदद के लिए 100 प्रति-त सी.एल.टी.एस. प्रशिक्षक का टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया था। इस टीम द्वारा अच्छा कार्य किया गया जिससे दिसंबर 2015 तक 30 प्रतिशत स्वच्छता आच्छादन पहुंच गया। और बहुत तेजी से राजनांदगांव के पुरे जिले को सी. एल.टी.एस. की स्थापना के 35 माह बाद 26 जनवरी 2017 को ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया ।

अध्ययन का उद्देश्य :-

क्षमता निर्माण : जिला स्तर पर पुरुष और महिला दोनों के लगभग 100 सदस्यों की एक टास्क फोर्स टीम की पहचान की गई और उन्हें सी.एल.टी.एस. पद्धति और कार्य प्रणाली पर प्रशिक्षित किया गया । जिला स्तर पर प्रशिक्षित टीम के सदस्यों द्वारा प्रमुख रूप से सी.एल.टी.एस. ट्रिगरिंग टूल्स और तकनीको से प्रशिक्षित समुदाय प्रेरक और अनुपत्ती अभ्यास को शामिल समुदायों को ओ.डी.एफ. के स्थिति तक ले जाने तक लोगों को व्यवहार में परिवर्तन पर ध्यान दिया गया। इस टीम के लिए प्रथम 5 दिवसीय प्रशिक्षण जनवरी 2015 में राजनांदगांव जिला स्तर पर आयोजन किया गया था। जिसके बाद टीम को मोहला ब्लॉक के ग्राम गोटाटोला में तैनात किया गया। इस टीम के द्वारा ग्राम स्तर पर ग्रामीणों का व्यवहार परिवर्तन किया गया जिसमें सुकालुराम ने 5 दिन में अपने घर पर व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करवाया। सुकालुराम ने गर्व के साथ कहा “आत्म सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है और स्वाभिमान के लिए वह कुछ भी कर सकता है” उनसे प्रेरित होकर पुरे गांव में शौचालय निर्माण होने लगा। यह एक कहानी के रूप में लिया और इस कहानी से प्रेरित होकर जल्द ही आस पास के ग्रामों में बात फैल गई और यह एक मुहिम में शामिल हो गया। जिला स्तर के अधिकारियों के दौरे और उनके बैठने, सुनने और स्थानीय स्तर के नेताओं से सीखने से उत्कृष्ट प्रेरणा और प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। (चैप्टर-2009) इसी तरह जिला

स्तरीय अधिकारियों और समुदाय स्तर के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया और इसी के माध्यम से सी.एल.टी.एस. को प्रभावी रूप से लागू किया गया ।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय :-

राजनांदगांव जिला जो पूर्व में दुर्ग जिले से अलग होकर 1973 में नया जिला बना पहले राजनांदगांव जिले को नादघाट या नादगांव के नाम से जाना जाता था। भारत में छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर, 2000 को हुआ है। राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ की जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, जिसमें 9 विकासखंड सम्मिलित हैं। उनमें से मानपुर, मोहला एवं अम्बागढ़ चौकी आदिवासी ब्लॉक है तथा छुईखदान, राजनांदगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ एवं छुरिया सामान्य ब्लॉक के रूप में स्थित हैं। राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र राज्य की सीमा के साथ लगा हुआ है। जिले में 2011 की जनगणना अनुसार 15 लाख 37 हजार जनसंख्या निवासरत् है। ब्लॉक मानपुर, मोहला एवं अम्बागढ़ चौकी में 60: से अधिक आदिवासी निवासरत् हैं। पुरे जिले में 813 ग्राम पंचायतें तथा 1647 ग्राम हैं जिसमें से 43 ग्राम विरान स्थिति में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की प्राथमिक इकाई है।

प्रथम ओ.डी.एफ. ग्राम पंचायत गोटाटोला जनपद पंचायत मोहला को खुले में शौच मुक्त घोषणा किया गया । वि.खं. मोहला के इस ग्राम पंचायत ने सी.एल.टी.एस. के क्रियान्वयन के बहुत सकारात्मक परिणाम दिखा। जिसमें स्पेशल 26 युवा क्रिकेट टीम के द्वारा 1 माह के अन्दर ओ.डी.एफ. ग्राम घोषणा कराया गया । स्पेशल 26 के सहयोग और कार्य कुशलता प्रभावी समुदाय ट्रिगरिंग सत्र और निरंतर अनुभवी कार्यवाही से सफलता मिली इसमें प्रमुख खिलाड़ी स्पेशल 26 के युवाओं के लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में सामने आ पाये जिन्होंने उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त किया ग्राम पंचायत ने औपचारिक रूप से 1 अप्रैल 2015 को खुद को ओ.डी.एफ. घोषित किया और उसके बाद मई को एक भव्य ओ.डी.एफ. उत्सव मनाया गया ।

शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध पत्र तथ्यों के संकलन एवं वि-लेखन पर आधारित है। इससे सम्बन्धित तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक तथ्य हेतु साक्षात्कार, अवलोकन एवं अनुसूची का उपयोग किया गया है द्वितीयक स्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकों, पत्र, पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया साथ ही विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है।

मई 2015 में यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें जिला, जनपद पंचायत स्तर के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य ग्राम पंचायतों के लोगों को आमंत्रित किया गया था। यह आयोजन फिर से अन्य ग्राम पंचायतों को खुल में शौच मुक्त हेतु खुद को तैयार करने और ओ.डी.एफ. ब्लॉक की दिश में मिलकर काम करने के लिए कए प्रेरणाकारक सिद्ध हुआ।

संस्थागत सशक्तिकरण :-

ग्राम पंचायत गोटोटोला, वि.खं. मोहला की सफलता ने अन्य ग्राम पंचायतों में एक जन आन्दोलन का नेतृत्व किया जिससे जल्द ही प्रेरित होकर अन्य ग्राम पंचायत के सरपंच और जन समुदाय के नेता चाहते थे कि उनके ग्राम पंचायत में भी सी.एल.टी.एस. लागू हो और उनके ग्राम पंचायत भी ओ.डी.एफ. हो सके। ऐसे ग्राम पंचायतों की पहचान जिला स्वच्छ भारत मिशन द्वारा की गई और सी.एल.टी.एस. अभियान शुरू करने के लिए सामुदायिक प्रेरकों को तैनात किया गया। चूंकि यह कार्य के लिए समर्पित टास्क फोर्स की आवश्यकता थी यूनिसेफ सलाहकारों द्वारा जिला स्वच्छ भारत मिशन को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर समूह बनाने का सुझाव दिया गया था। ताकि पुरे जिला में सी.एल.टी.एस. का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किये जाने के लिए समूह/प्रेरक/संस्थागत लोगों की एक चैनल तैयार किया जा सके ग्रामीण विकास, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया के लोगों को तब इसमें शामिल कर उन्हें सी.एल.टी.एस. प्रनिक्षक/प्रेरक के रूप में प्रशिक्षित किया गया। स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों, नेताओं और स्कूली बच्चों के बीच स्वच्छता के बारे में प्रचार-प्रसार कर महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया तथा व्यवहार परिवर्तन करने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए कई प्रकार का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस तरह जिले में स्वच्छता को सबसे उपर रखकर महत्वपूर्ण कार्यक्रम पुरे मिशन मोड में जिला कलेक्टर एवं सी.ई.ओ. जिला पंचायत, जिला राजनांदगांव के नेतृत्व में पुरा किया गया।

ग्राम पंचायत स्तर पर ओ.डी.एफ. जन चौपाल :-

सभी समुदाय अपने प्रमुख त्रौहारों या अवसरों और उपलब्धियों को चिन्हांकित करने के लिए ओ.डी.एफ. बनाने प्रतिगांव जन चौपाल का आयोजन किया जाने लगा। इस आयोजन किये जाने लगे और स्कूल में शौच जाने की प्रथा को धीरे-धीरे लगाम लगने लगा। तथा स्कूलों में शौच जाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक दूसरों का सहयोग किये जाने लगे। जिला अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों और प्राकृतिक नेताओं की उपस्थिति ने इन जन चौपाल को अन्य सभी के लिए बेहद आकर्षक और प्रेरक बना दिया। आदिवासी तथा अन्य लोगों के चेहरों पर स्वाभिमान और सफलता का भाव झलकने लगा। स्कूली बच्चों एवं रंगमंच के कार्यक्रम ने उत्सव को और अधिक रंगीन और मनोरंजक बना दिया।

इस तरह ग्राम पंचायत में प्रोजेक्टर के माध्यम से सफलता की कहानी जन चौपाल में दिखाने लगे तथा जिला प्रशासन द्वारा नगद प्रोत्साहन और प्रशस्ती पत्र जैसे जन प्रतिनिधियों से पुरस्कार प्राप्त करने की घोषणा भी किया गया । कुछ ग्राम पंचायतों में भी आयोजन में विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर भी शुरुआत किया जाने लगा ।

शोध समस्या :-

सी.एल.टी.एस. लागू करने तथा शौचालय बनाने में बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ा -

1. मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, छुईखदान ब्लॉक के कुछ हिस्सों में नक्सलियों का डर।
2. आवागमन की असुविधा होना जिससे ग्राम स्तर पर शौचालय निर्माण हेतु सामग्री की आपूर्ति नहीं होना।
3. निर्माण हेतु आसानी से सामग्री नहीं मिलना।
4. ग्राम स्तर पर रूढ़ीवादी परंपरा होना जो कि शौचालय निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करना।
5. सी.एल.टी.एस. को आसानी से ग्रहण नहीं करना।

इस तरह से बहुत बाधाओं के उत्पन्न होने तथा कुछ ग्राम पंचायतों में जन चौपाल आयोजित करना असंभव था। किसी भी स्थिति में इस प्रकार के ग्राम पंचायत के लोगों के साथ सम्पर्क किया जाना संभव नहीं था।

निष्कर्ष :-

जनजातीय क्षेत्र में समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता पद्धति (सी.एल.टी.एस.) जिला राजनांदगांव में यह हस्ताक्षेप प्रभावी परिणाम निम्न निष्कर्ष को चिन्हांकित है :-

1. सी.एल.टी.एस. दुर्गम और अंदरूनी आदिवासी समुदायों तथा आसानी से पहुंचने के लिए ओ.डी.एफ. गांव बनाने के लिए जन आंदोलन को बनाने के लिए एक सशक्त तरीका उभर का सामने आया।
2. राजनांदगांव क्षेत्र के आदिवासी समुदायों में ओ.डी.एफ. परिणामों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खुले में शौच के हानिकारक परिणामों और शौचालय के उपयोग के कथित महत्व के बारे में एक अति महत्वपूर्ण जागरूकता सबसे शक्ति-शाली कारक रही है।
3. राजनांदगांव जिले में जनजातीय समुदायों की परंपरा, संस्कृतियों, प्रथा, त्यौहार, विश्वास और जीवन शैली की एक समुचित प्रभाव समुदाय की कुंजी है जो जमीन पर स्थायी ओ.डी.एफ. परिणाम की ओर ले जाती है।

4. अभिनव प्रयास और स्थानीय रूप से लागू उपकरणों की मदद से प्रभावी समुदाय के राजनांदगांव जिले में आदिवासी समुदायों के बीच व्यवहार परिवर्तन लाया।

सूझाव :-

धीरे धीरे बाधाओं को पार कर जैसे जैसे अन्य ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. घोषित होने लगे, दीवार पेंटिंग, फिल्म प्रदर्शनी, ओ.डी.एफ. जन चौपाल का आयोजन, स्कूली बच्चों तथा महिला समूहों द्वारा रैलियों और स्वच्छता पर सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से संचार में इन दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में रहने वाले समुदायों को आकर्षित करने के लिए एक कारगर उपकरण के रूप में काम किया। धीरे धीरे इन ग्राम पंचायतों को लोगों ने भी वहां उपलब्ध सामग्री से अपने दम पर शौचालय बनाना शुरू किया गया।

संदर्भ सूची :-

- 1- डॉ. मो. इसरार खान, सर्वेश कुमार : स्वच्छ भारत अभियान का ग्राम स्तरीय सूक्ष्म अध्ययन, ISSN:2455-5746, Impact Factor: RJIF 5.34, Volume 1; Issue 8; August 2016; Page no. 55-61.
- 2- डॉ. अरुण कुमार ओझा, रीवा जिले में युवाओं में स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जागरूकता व अवबोधन का अध्ययन : ISSN:2455-5746, Impact Factor: RJIF 5.34, Volume 2; Issue 4; July 2017; Page no. 264-266.
3. नरेन्द्र सिंह तोमर : स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव, कुरुक्षेत्र, अंक 01 नवंबर, 2018
4. पाण्डेय, संदीप कुमार, स्वच्छ भारत अभियान में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्ता, योजना 2015; 59(1): 15.
- 5- डॉ. राहुल शर्मा, संगीता पाटनवार : ISSN:2455-6157, Impact Factor: RJIF 5.12, Volume 3; Issue 2; March 2018; Page no. 553-555.
6. अरुण जेटली : स्वच्छता में निवेन का अर्थशास्त्र, कुरुक्षेत्र, अंक 12, अक्टूबर 2017.
7. सिंह आशुतोश कुमार : स्वच्छ भारत से ही साकार होगा स्वस्थ भारत, योजना 2015, 59(1):37.41.
8. स्वच्छता की यात्रा : नव भारत टाईम्स, 03 अक्टूबर, 2019
- 9- <http://em.wikipedia.org/wiki/opendefecation>
10. <http://swachhbharat.mygov.in>